अजीत कुमार रथ

बनाम

ओरीसा राज्य

नवंबर 2,1999

[एस. सागर अहमद और आर. पी. सेठी, जे. जे.]

सेवा विषय-- ओरिसा सर्विस ऑफ इंजीनियर रूल्स, 1941-नियम 26-एक ही वर्ष में एक ही पद पर नियुक्त प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच अंतर-वरिष्ठता का निर्धारण-यदि उसी दिन नियुक्त किया जाता है, तो पदोन्नतियां सीधी भर्तियों के लिए वरिष्ठ रैंक करेंगी।-नियुक्ति नियुक्ति की वास्तविक तिथि से संबंधित है न कि उस तिथि से जिस पर पद खाली हुआ-नियमों के अनुसार नियुक्त होने पर नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता की गणना की जाएगी पदोन्नति पर तदर्थ पद में प्रदान की गई सेवा, लोक सेवा आयोग की मंजूरी लंबित होने पर, नियमित सेवा के रूप में मानी जाएगी यदि पदोन्नति नियमों के अनुसार नियमित थी, हालांकि अनंतिम आधार पर अनुमोदन लंबित है, और पदधारी उक्त पद पर निर्बाध रूप से जारी रहा-इस तरह की तदर्थ सेवा को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा-सीधे भर्ती द्वारा पद पर नियुक्त होने में अपीलार्थी की विफलता पदोन्नत होने के लिए कोई बाधा नहीं है।

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985-- धारा 22 (3) (जे)-समीक्षा-पुनर्विलोकन की शक्ति वही है जो आदेश 47

सीपीसी के साथ पठित धारा I 14 के तहत न्यायालय को दी गई है और आदेश 47 द्वारा सशर्त है-समीक्षा आवेदन पर केवल नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर विचार किया जा सकता है जो उचित परिश्रम के बाद भी आवेदक द्वारा आदेश दिए जाने के समय ज्ञान के भीतर नहीं था/ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था या जब रिकॉर्ड के सामने या किसी पर्याप्त कारण से कोई त्रुटि/ गलती स्पष्ट हो-वाक्यांश "कोई अन्य पर्याप्त कारण" का अर्थ है आदेश 47 नियम I-कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908 धारा 114 में आदेश 47 के साथ पठित पर्याप्त रूप से समान कारण।

अपीलार्थी को पर्यवेक्षक/ अधीनस्थ सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था। उड़ीसा में अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा में इंजीनियर। 7-8-1972 को उन्हें अन्य लोगों के साथ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था। इंजीनियर (सिविल) नियमों के अनुसार, नियमित आधार पर। हालाँकि उनकी पोस्टिंग को उड़ीसा लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाना था जिसने अंततः 17-7-1976 को ही मंजूरी दी। पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच अंतर-वरिष्ठता के संबंध में एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिन्हें 1972 में एक ही पद पर नियुक्त किया गया था और अपीलार्थी और अन्य लोगों द्वारा ओरिसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी को प्रत्यक्ष भर्तियों से वरिष्ठ मानकर उसके पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन बाद में समीक्षा में, उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए और इस

न्यायालय के एक संवैधानिक पीठ के फैसले की अनदेखी करते हुए, अपने निष्कर्ष को उलट दिया। पीड़ित, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील यह तर्क देते हुए दायर की कि अधिकरण एक बार इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय द्वारा निर्देशित निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद, उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए और संविधान पीठ के निर्णय की अनदेखी करते हुए एक विपरीत निष्कर्ष पर नहीं आ सकता था कि समीक्षा में निर्णय नियम 26 और उसके संशोधनों को गलत तरीके से पढ़ता है। प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि संविधान पीठ का निर्णय मामले पर लागू नहीं था; कि वरिष्ठता की गणना केवल मूल नियुक्ति की तारीख से की जानी थी जैसा कि नियमों में निर्दिष्ट है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने ये निर्णय सुनाया:

1. अधिकरण द्वारा मुख्य निर्णय लिखते समय यह तथ्य पाया गया है कि अपीलार्थी को सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था। स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियमों के अनुसार इंजीनियर और लोक सेवा आयोग की सहमति लंबित रहने तक तदर्थ पदोन्नति दी गई थी और चूंकि इस निष्कर्ष को बरकरार रखा गया है, इसलिए अपीलार्थी, जिसे 1972 में पदोन्नत किया गया था, किस वर्ष प्रत्यर्थी सं. 2 से 11 भी बनाए गए थे, जो प्रत्यर्थी संख्या से वरिष्ठ होंगे। 2 से 11 तक। (319-D-E)

2. अधिकरण ने पाया कि चूंकि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी नं. 12 को 1976 में उड़ीसा लोक सेवा आयोग की सहमति पर मूल नियुक्ति दी गई थी, वे 1972 से अपनी वरिष्ठता की गणना नहीं कर सकते हैं और इसलिए, उत्तरदाताओं से कनिष्ठ होंगे। इसी आधार पर न्यायाधिकरण ने अपने पहले के फैसले की समीक्षा की और इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का पालन नहीं किया। उड़ीसा सर्विस ऑफ इंजीनियर रूल्स के नियम 26 ने अपने अपरिवर्तित रूप में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता की गणना के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन इस नियम में 1967 में एक संशोधन किया गया जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि यदि सहायक के पद। इंजीनियरों को विशेष वर्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा भरा जाता था, जिन्हें पदोन्नत किया जाता था, वे सीधे भर्ती किए गए लोगों से वरिष्ठ रैंक पर होते थे। न्यायाधिकरण द्वारा इस संशोधन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है क्योंकि समीक्षा पर पारित विवादित निर्णय में 1967 के संशोधन का कोई संदर्भ नहीं है। अधिकरण ने केवल 1974 के संशोधन का निर्देश किया है और यद्यपि यह संशोधन 1.1.1972 से पूर्वव्यापी प्रभाव से किया गया था, अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि यह संभावित प्रकृति का था और 1.1.1972 से प्रभावी नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप यह अपरिवर्तित नियम 26 पर निर्भर था जिसके तहत वरिष्ठता को मूल नियुक्ति की तारीख से गिना जाना था [311-जी, एच; 312-ए-डी]

3. ऐसा प्रतीत होता है कि नियमों के आधार पर, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी नं. 12 को सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। लोक सेवा आयोग की सहमति के अधीन तदर्थ आधार पर इंजीनियर। यह 8-2-1972 को किया गया था। उड़ीसा लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त होने पर, 17 जुलाई, 1976 को एक नई अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी और प्रत्यर्थी नं. 12 को नियमित आधार पर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। इंजीनियर। पदोन्नति नियमों के अनुसार की गई है, 1972 से 1976 तक की पूरी अवधि, जब अपीलार्थी को आयोग की सहमति से नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, को अपीलार्थी विस्का की प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं की वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा। [312-ई-एफ]

सीधी भर्ती कक्षा-II इंजीनियरिंग। ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड ओआरएस। v. महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [1990] 2 SCR 900; O.P. सिंह बनाम भारत संघ (1984) 4 एस. सी. सी. 450; और पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। v. अघोर नाथ डे और अन्य, [1993] 3 धारा 371, पर भरोसा किया

केशव देव और अन्र. v. यूपी राज्य। और अन्य, [1999) एल एससीसी 280 और चंद्रकिशोर सिंह बनाम मणिपुर राज्य और अन्य, जेटी, (1999) 7 एससी 576, संदर्भित किया गया है।

वी. श्रीनिवास रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, [1995] सप. I SCC 572; V.P. श्रीवास्तव और ओआरएस। v. एमपी का राज्य। , [1996] 7 एस. सी. सी. 759; मसूद अख्तर खान और अन्य। v. मध्य प्रदेश और अन्य राज्य, [1990) 4 एससीसी 24 और अनुराधा मुखर्जी और अन्य। v. भारत संघ और अन्य, (1996) 9 एससीसी 59, विशिष्ट।

4. प्रत्यर्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया था कि वे 1970 और 1971 से अपनी वरिष्ठता की गणना करने के हकदार थे क्योंकि उन्हें उन वर्षों की रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था। यह याचिका पूरी तरह से निराधार है और बिना किसी सार और योग्यता के खारिज की जा सकती है [310-डी, ई, एफ)

जगदीश च. पटनायक और ओआरएस। v. स्टेट ऑफ ऑरिसा एंड ओआरएस, 11998] 4 एससीसी 456 एआईआर (1998) एससी 1926, पर भरोसा किया गया।

5. पुनरीक्षण कार्यवाहियों में, अधिकरण इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से भटक गया जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और उस निर्णय को फिर से लिखने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा विवाद का अंत में निर्णय लिया गया था। यह अधिनियम की धारा 22 (3) (टी) के तहत समीक्षा का दायरा नहीं है। प्रावधानों से संकेत मिलता है कि अधिकरण को उपलब्ध समीक्षा की शक्ति वही है जो आदेश 47 सीपीसी के साथ पठित धारा 114 के तहत

न्यायालय को दी गई है। शक्ति निरपेक्ष नहीं है और आदेश 47 में बताए गए प्रतिबंधों से सुरक्षित है। शक्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति के नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर किया जा सकता है, जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, उसके ज्ञान में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब रेडर बनाया गया था। रिकॉर्ड के सामने दिखाई देने वाली किसी गलती या त्रुटि के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। पुनरीक्षण का दावा नहीं किया जा सकता है या केवल एक नई सुनवाई या तर्क या पहले लिए गए गलत दृष्टिकोण के सुधार के लिए नहीं कहा जा सकता है, अर्थात, पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग केवल कानून या तथ्य की एक पेटेंट त्रुटि के सुधार के लिए किया जा सकता है जो इसे स्थापित करने के लिए किसी विस्तृत तर्क की आवश्यकता के बिना सामने आती है। आदेश 47 नियम 1 में प्रयुक्त "कोई अन्य पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति का अर्थ है नियम में निर्दिष्ट कारणों के लिए पर्याप्त रूप से समान कारण। स्पष्ट त्रुटि को सुधारने या आदेश 47 में निर्धारित किसी आधार पर आधारित प्रयास को छोड़कर कोई अन्य प्रयास, अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण को अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग होगा। [317-डी-एच]

6. उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय 12 मार्च, 1985 को दिया गया था, जो कि 1990 में संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय से कई साल पहले दिया गया था। संविधान पीठ के

निर्णय के साथ-साथ इस न्यायालय के अन्य निर्णयों के आधार पर, उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रभावकारिता पूरी तरह से समाप्त हो गई है और अधिकरण के लिए पुनरीक्षण निर्णय लिखते समय संविधान पीठ के निर्णय से पहले उस निर्णय पर भरोसा करने का कोई अवसर नहीं था। [318-बी-डी]

डायरेक्ट रिक्रूट क्लास इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन एंड ओआरएस। v. महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [1990] 2 एससीआर 900, संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 1995 का 11811।

भुवनेश्वर में उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के 31.8.95 दिनांकित निर्णय और आदेश से M.P. नं. 1993 का 779.

अपीलार्थी के लिए पी.पी. राव, के. महालिक, देबासिस मोहंती, के.एन. त्रिपाठी, जे.आर. दास, जमशेद बे, अजय तलेसरा और ए. क़मरुद्दीन।

पी.एन. मिश्रा, आर.एस. जेना, राज कुमार मेहता और श्रीमती एम. सारदा, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

एस. सागीर अहमद, जे. - अपीलार्थी, जिसने इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की थी, को अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा में 23-3-1965 को एक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो उड़ीसा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स रूल्स, 1941 (संक्षेप में "नियम") द्वारा शासित और विनियमित है। कई अन्य पर्यवेक्षक थे जो केवल डिप्लोमा धारक थे। 1-5-1965 को और उससे पहले, अपीलार्थी को अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा के अन्य सदस्यों से अलग करने के लिए कनिष्ठ अभियंता के रूप में फिर से नामित किया गया था जो केवल डिप्लोमा धारक थे। उनके अनुसार, यह केवल एक कार्यात्मक पदनाम था। इस पदनाम के बावजूद, उन्हें दिनांक 12-5-1969 के आदेश में अधीनस्थ सहायक अभियंता के रूप में वर्णित और नामित किया गया था, जिसके द्वारा उनका स्थानांतरण किया गया था। उड़ीसा राज्य में पर्यवेक्षकों को निर्विवाद रूप से अधीनस्थ सहायक अभियंता के रूप में जाना जाता है।

7-8-1972 को कई अन्य अधिकारियों के साथ अपीलार्थी को तदर्थ आधार पर सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में पदोन्नत किया गया। चूंकि सहायक अभियंता (सिविल) के पद उड़ीसा लोक सेवा आयोग के दायरे में थे, इसलिए पदोन्नति के क्रम में यह संकेत दिया गया था कि पदोन्नति छह महीने की अवधि के लिए या उड़ीसा लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए थी। सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर अपीलार्थी की सेवाओं को दिनांक 17-7-1976 के आदेश द्वारा नियमित किया गया था क्योंकि इस बीच उड़ीसा लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त हो गई थी।

उत्तरदाता 2 से 11 (संक्षेप में " उत्तरदाता") और अन्य अधिकारियों को 7-1-1972 और 12-9-1972 के बीच विभिन्न तिथियों पर सीधे सहायक अभियंता के रूप में भर्ती किया गया था।

चूंकि एक ओर अपीलार्थी सहित प्रोन्नति अधिकारियों और दूसरी ओर प्रत्यर्थियों सहित प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच वरिष्ठता का विवाद उत्पन्न हुआ था, इसलिए अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी 12 के साथ उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर की जिसके द्वारा उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी वरिष्ठता सूची को चुनौती दी क्योंकि इस वरिष्ठता सूची के आधार पर ही कुछ प्रत्यर्थियों को कार्यकारी अभियंताओं और सहायक कार्यकारी अभियंताओं के पदों पर पदोन्नत किया गया था। याचिका में यह दावा किया गया था कि चूंकि अपीलार्थी को 1972 में सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था और प्रत्यर्थियों को भी संयोग से नियुक्त किया गया था, हालांकि उसी वर्ष, अर्थात् 1972 में, सहायक अभियंता के रूप में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा, अपीलार्थी नियमों के नियम 26 के कारण सहायक अभियंता के संवर्ग में प्रत्यर्थियों से वरिष्ठ रैंक का होगा, जो विशिष्ट और स्पष्ट शब्दों में प्रदान करता है कि यदि पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती एक ही कैलेंडर वर्ष में की जाती है, तो पदोन्नत अधिकारी प्रत्यक्ष भर्तियों से वरिष्ठ रैंक के होंगे।

अधिकरण ने दिनांक 4-1-1993 के अपने निर्णय द्वारा दावा याचिका को इस निष्कर्ष के साथ अनुमति दी कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12 को 1972 में पदोन्नत किया गया था जो उसी वर्ष प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा सहायक अभियंताओं के रूप में

नियुक्त किए गए प्रत्यर्थियों से वरिष्ठ पद पर होंगे। प्रत्यर्थी (उड़ीसा राज्य) को वरिष्ठता सूची को सही करने और अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12 को सहायक कार्यकारी अभियंता और कार्यकारी अभियंता के पदों पर पदोन्नति के लिए उस तारीख से विचार करने का निर्देश दिया गया था जब वर्तमान प्रत्यर्थी सहित उनके कनिष्ठों को उन पदों पर पदोन्नत किया गया था।

तत्पश्चात, प्रत्यर्थियों ने अधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे 31-8-1995 को अनुज्ञात किया गया और अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12 को प्रत्यर्थियों और 1972 के अन्य सीधे भर्ती किए गए सहायक अभियंताओं से कनिष्ठ ठहराया गया। समीक्षा याचिका को उसी सेवा से संबंधित उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले के कारण अनुमति दी गई थी, जिसके बाद न्यायाधिकरण द्वारा पारित किया गया था और इसके द्वारा पारित पहले के फैसले को दरकिनार कर दिया गया था। यह अधिकरण का यह निर्णय है जिसे इस अपील में हमारे समक्ष चुनौती दी गई है।

श्री P.P. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील राव ने तर्क दिया है कि एक बार प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा वरिष्ठता के विवाद का निपटारा किया गया था। ऑफिसर्स एसोसिएशन। v. महाराष्ट्र राज्य [(1990) 2 एस. सी. सी. 715:1990 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 339: (1990) 13 ए. टी. सी. 348: (1990) 2 एस. सी. आर. 900: ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1607] यह अधिकरण के लिए अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए केवल इसलिए

खुला नहीं था क्योंकि उड़ीसा उच्च न्यायालय का एक निर्णय था जिसमें एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया था, जिसे अधिकरण द्वारा पहले नहीं देखा गया था। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ऊपर निर्दिष्ट संविधान पीठ के निर्णय के विपरीत था, इसलिए इसका कोई बाध्यकारी मूल्य नहीं था और इसलिए, भले ही मुख्य निर्णय देते समय न्यायाधिकरण द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस निर्णय को किसी भी मामले में संविधान पीठ के बाद के फैसले के मद्देनजर नजरअंदाज किया जाना था। श्री राव ने आगे तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा याचिका पर पारित निर्णय वरिष्ठता के नियम के गलत अध्ययन पर आधारित है। यह तर्क दिया जाता है कि नियम 26, जो पदोन्नत और सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता से संबंधित है, में दो संशोधन किए गए थे; एक 1967 में और दूसरा 1974 में। लेकिन न्यायाधिकरण, जिसने मुख्य निर्णय लिखने के समय 1967 के संशोधन को नोटिस किया था, ने समीक्षा निर्णय लिखते समय उस संशोधन को नजरअंदाज कर दिया। यह इंगित किया गया है कि यह अधिकरण की एक गलती है जो पुनरीक्षण याचिका पर उसके द्वारा पारित पूरे निर्णय को दूषित करती है। यह भी तर्क दिया जाता है कि ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग में इस न्यायालय के फैसले में अंतर करने में पूरी तरह से त्रुटि की थी। ऑफिसर्स एसोसिएशन। मामला [(1990) 2 एससीसी 715:1990 एससीसी (एल एंड एस) 339: (1990) 13 एटीसी 348: (1990) 2 एससीआर 900: एआईआर 1990 एससी 1607]।

प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने बताया है कि न्यायाधिकरण द्वारा मूल रूप से पारित निर्णय में अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटियां थीं और इसलिए, न्यायाधिकरण ने समीक्षा याचिका को अनुमति दी और एक नया निर्णय पारित किया जिसमें सही कानूनी स्थिति निर्धारित की गई थी और प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी से वरिष्ठ माना गया था। यह इंगित किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग में निर्धारित कानून। ऑफिसर्स एसोसिएशन। मामला [(1990) 2 एससीसी 715:1990 एससीसी (एल एंड एस) 339: (1990) 13 एटीसी 348: (1990) 2 एससीआर 900: एआईआर 1990 एससी 1607] इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा क्योंकि तत्काल मामले में, वरिष्ठता का निर्धारण केवल नियम 26 के आधार पर किया जाना था और इस न्यायालय के निर्णय सहित किसी अन्य आधार पर नहीं। चूंकि नियम 26, जैसा कि 1974 में इसके संशोधन से पहले था, विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि वरिष्ठता को मूल नियुक्ति की तारीख से गिना जाएगा, इसलिए अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12, यह तर्क दिया जाता है, उस अवधि को गिनने के हकदार नहीं थे जिसके लिए उन्होंने अपनी वरिष्ठता के लिए सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ आधार पर काम किया था। न्यायाधिकरण को मूल नियुक्ति की तारीख से उनकी वरिष्ठता की गणना करने और सहायक अभियंता के पद पर तदर्थ आधार पर काम करने की अवधि को छोड़कर न्यायसंगत ठहराया गया था।

पक्षों के बीच विवाद को समझने के लिए, नियम 26 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक होगा, क्योंकि यह मूल रूप से 1967

और 1974 में संशोधनों के बाद अपनाए गए आकार के रूप में भी खड़ा था। ये नीचे दिए गए हैं:

मूल नियम 26

> वरिष्ठता-कार्यकारी और सहायक अभियंता के पद पर वरिष्ठता का निर्धारण संबंधित श्रेणी में अधिकारी की मूल नियुक्ति की तारीख से किया जाएगा, चाहे उसके द्वारा लिया गया वेतन कुछ भी हो। उसी तिथि पर नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता राज्यपाल द्वारा तय की जाएगी।

1967 में संशोधित नियम 26

> जब अधिकारियों की भर्ती उसी वर्ष (कैलेंडर वर्ष) के दौरान पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा की जाती है, तो पदोन्नत अधिकारियों को सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों से वरिष्ठ माना जाएगा, चाहे उनकी नियुक्ति में शामिल होने की तारीख कुछ भी हो।

1974 में संशोधित नियम 26 (1-1-1972 से पूर्वव्यापी प्रभाव)

> "26. (1) जब अधिकारियों को उसी वर्ष के दौरान पदोन्नति द्वारा और प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भर्ती किया जाता है, तो पदोन्नत अधिकारियों को नियुक्ति में शामिल होने

की उनकी तारीखों के बावजूद सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों से वरिष्ठ माना जाएगा।

(2) पदोन्नत अधिकारियों के दो समूहों के बीच, उप-सहायक अभियंता के पद से पदोन्नत होने वाले लोग कनिष्ठ अभियंता के पद से पदोन्नत होने वालों से वरिष्ठ होंगे।

(3) उप-नियम (1) और (2) के प्रावधानों के अधीन अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण आयोग द्वारा तैयार की गई सूचियों में उनके नाम के क्रम के अनुसार किया जाएगा।

संशोधित और संशोधित नियम 26 के निहितार्थ पर विचार करने से पहले, हम यह इंगित कर सकते हैं कि अन्य बातों के साथ-साथ उत्तरदाताओं द्वारा समीक्षा की मांग की गई थी कि अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता होने के नाते 1972 में सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था। यह इंगित किया गया है कि जब सहायक अभियंता के पद पर अपीलार्थी की पदोन्नति के लिए उड़ीसा लोक सेवा आयोग की सिफारिश की गई थी और आयोग की सहमति मांगी गई थी, तो आयोग ने आपत्ति जताई कि यह संभव नहीं होगा क्योंकि अधीनस्थ अभियंता सेवा के संवर्ग में "कनिष्ठ अभियंता" जैसा कोई संवर्ग नहीं था जिससे सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति की जा सके। आयोग ने नियमों में संशोधन का सुझाव दिया और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने नियम में संशोधन किया और यह प्रावधान किया कि सहायक अभियंता

के पद पर अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा के सदस्यों के साथ-साथ कनिष्ठ अभियंताओं में से भी पदोन्नति की जा सकती है।

इसके संशोधन से पहले नियम 6 में यह प्रावधान किया गया था कि सहायक अभियंता के पद पर भर्ती आंशिक रूप से प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा और आंशिक रूप से दो घरेलू स्रोतों, पुराने उच्च अधीनस्थ इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान और अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा से पदोन्नति द्वारा की जाएगी। इस नियम के आधार पर ही पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के समय अधिकरण के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि सहायक अभियंता के पद पर "कनिष्ठ अभियंताओं" में से पदोन्नति नहीं की जा सकती क्योंकि उपरोक्त नियम में "कनिष्ठ अभियंताओं" को "स्रोत" या "फीडर संवर्ग" के रूप में इंगित नहीं किया गया था। रिलायंस को इस उद्देश्य के लिए रिट याचिकाओं में उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले पर रखा गया था (OJCs Nos. 921, 922 and 923 of 1980). यह तर्क दिया गया था कि 1974 में नियम 6 में संशोधन किया गया था और सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के स्रोतों में से एक का गठन करने के लिए नियम में "कनिष्ठ अभियंताओं" को शामिल किया गया था। परन्तु संशोधन प्रत्याशित प्रकृति का था और इसलिए यह इंगित किया गया था कि अपीलार्थी 7-12-1974 से प्रभावी सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होगा, जब नियम में संशोधन किया गया था, जैसा कि उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर निर्दिष्ट रिट याचिकाओं में अभिनिर्धारित किया गया था।

हालांकि, न्यायाधिकरण ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा से संबंधित उप-सहायक अभियंता केवल डिप्लोमा धारक थे, जबकि अपीलार्थी, जिसके पास इंजीनियरिंग में डिग्री थी, को जूनियर इंजीनियर माना जाता था, और यह सोचना बेतुका होगा कि हालांकि डिप्लोमा धारक पदोन्नति के लिए पात्र थे, इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले व्यक्ति अपात्र थे। न्यायाधिकरण ने पाया कि अपीलार्थी 1972 में भी सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था। समीक्षा निर्णय में भी इसे दोहराया गया था।

न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थियों की ओर से यह भी प्रतिवाद किया गया था और यहां यह भी दोहराया गया है कि प्रत्यर्थियों को 1970 और 1971 से उनकी वरिष्ठता की गणना करने का अधिकार है क्योंकि उन्हें उन वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। यह इंगित किया गया है कि सहायक अभियंता के पदों पर सीधी भर्ती के लिए 1970-71 में विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा 6-12-1971 को जारी किया गया था और उसके बाद परिणाम प्रकाशित किया गया था जिससे संकेत मिलता है कि सभी उत्तरदाताओं का चयन किया गया था। उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया गया। हालांकि, नियुक्ति का आदेश 3-1-1972 को पारित किया गया था। इसलिए प्रतिवादी इस आधार पर 1970 और 1971 से वरिष्ठता का दावा करते हैं कि उन्हें 1970 और 1971 की रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था। उनका दावा है कि उनकी वरिष्ठता पूर्व-दिनांकित हो सकती है।

यह याचिका पूरी तरह से निराधार है और बिना किसी सार और योग्यता के खारिज की जा सकती है। इस प्रश्न पर कानून पहले ही इस न्यायालय द्वारा जगदीश च में समझाया जा चुका है। पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य [(1998) 4 एस. सी. सी. 456:1998 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1156: ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1926] और यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि नियुक्ति रिक्ति की तारीख से संबंधित नहीं है। न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः (एस सी सी pp. 467-68, para 32)

> *"32. विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या उस वर्ष जिसमें रिक्ति उपार्जित होती है, क्या वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से कोई प्रासंगिकता हो सकती है, इस तथ्य के बावजूद कि व्यक्तियों की भर्ती कब की जाती है? इस पर श्री बनर्जी का तर्क है कि चूंकि अपीलार्थी को वर्ष 1978 में उत्पन्न रिक्तियों के संबंध में सहायक अभियंता के संवर्ग में भर्ती किया गया था, हालांकि वास्तव में नियुक्ति पत्र मार्च 1980 में ही जारी किया गया था, इसलिए उसे वर्ष 1978 की भर्ती माना जाना चाहिए और इस तरह वह वर्ष 1979 और 1980 के पदोन्नतों से वरिष्ठ होगा और वर्ष 1978 के पदोन्नतों से कनिष्ठ होगा। विद्वान वकील के अनुसार चूंकि भर्ती की प्रक्रिया में काफी लंबी अवधि लगती है क्योंकि लोक सेवा आयोग आवेदन, साक्षात्कार आमंत्रित करता है और अंत में उनका चयन करता है, जिसके बाद सरकार अंतिम निर्णय लेती है, इसलिए उस वर्ष की अनदेखी करना अतार्किक होगा*

जिसमें रिक्ति उत्पन्न हुई थी और जिसके खिलाफ भर्ती की गई थी। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उस वर्ष के बीच कुछ समय अंतराल होगा जब रिक्ति अर्जित होती है और उस वर्ष के बीच जब निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए अंतिम भर्ती की जाती है, लेकिन इससे न्यायालय को कुछ ऐसा शामिल करने का अधिकार नहीं मिलेगा जो नियम 26 के तहत वरिष्ठता के नियमों में नहीं है। नियम 26 के तहत जिस वर्ष रिक्ति उत्पन्न हुई और किस रिक्ति के खिलाफ भर्ती की गई है, उस पर प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच अंतर वरिष्ठता के निर्धारण के लिए बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसमें केवल यह कहा गया है कि कैलेंडर वर्ष के दौरान सहायक अभियंता के संवर्ग में सीधी भर्तियां उक्त संवर्ग में पदोन्नत भर्तियों से जूनियर होंगी। न्यायालय के लिए ऐसा कुछ आयात करना संभव नहीं है जो नियम 26 में नहीं है और इस प्रकार वरिष्ठता का एक नया नियम बनाना संभव नहीं है। इसलिए हम अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री बनर्जी के निवेदन से सहमत होने की स्थिति में नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका को अस्वीकार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से निर्णय के रूप में, जिसका एक हिस्सा ऊपर निकाला गया है, उसी सेवा नियमों से संबंधित है जिससे हम वर्तमान मामले में संबंधित हैं।

न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया एकमात्र तर्क और जिसके आधार पर उसने अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा की, वह

यह था कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 1972 में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए जाने की तारीख से प्रभावी रूप से अपनी वरिष्ठता की गणना करने के हकदार नहीं थे क्योंकि 1974 में नियमों में पेश किया गया संशोधन पूर्वव्यापी प्रकृति का नहीं था और अपरिवर्तित नियम केवल मूल नियुक्ति की तारीख से ही वरिष्ठता की अनुमति देता था। अधिकरण ने पाया कि चूंकि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12 को 1976 में उड़ीसा लोक सेवा आयोग की सहमति पर पर्याप्त नियुक्ति दी गई थी, इसलिए वे 1972 से अपनी वरिष्ठता नहीं मान सकते हैं और इसलिए वे प्रत्यर्थियों से कनिष्ठ होंगे। इस आधार पर ट्रिब्यूनल ने अपने पहले के फैसले की समीक्षा की और डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग में इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले का पालन नहीं किया। ऑफिसर्स एसोसिएशन। मामला [(1990) 2 एससीसी 715:1990 एससीसी (एल एंड एस) 339: (1990) 13 एटीसी 348: (1990) 2 एससीआर 900: एआईआर 1990 एससी 1607]। हम अधिकरण के तर्क से सहमत नहीं हैं।

नियम 26 ने अपने अपरिवर्तित रूप में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता की गणना के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन इस नियम में 1967 में एक संशोधन किया गया जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि यदि सहायक अभियंताओं के पदों को किसी विशेष वर्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा भरा जाता है, तो पदोन्नत किए गए लोग सीधे भर्ती किए गए लोगों से वरिष्ठ रैंक के होंगे। न्यायाधिकरण द्वारा इस संशोधन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है क्योंकि समीक्षा पर पारित

विवादित निर्णय में 1967 के संशोधन का कोई संदर्भ नहीं है। अधिकरण ने केवल 1974 के संशोधन का निर्देश किया है और यद्यपि यह संशोधन 1-1-1972 से पूर्वव्यापी प्रभाव से किया गया था, अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि यह संभावित प्रकृति का था और 1-1-1972 से प्रभावी नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप यह अपरिवर्तित नियम 26 पर निर्भर था जिसके तहत वरिष्ठता को मूल नियुक्ति की तारीख से गिना जाना था।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12 को दिनांक 7-8-1972 के आदेश द्वारा तदर्थ आधार पर छह महीने की अवधि के लिए या उनकी नियुक्तियों के लिए उड़ीसा लोक सेवा आयोग की सहमति उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था। उनका मामला लोक सेवा आयोग को भेजा गया जिसने उनकी नियुक्तियों के लिए अपनी सहमति दी और परिणामस्वरूप दिनांक 17-7-1976 के आदेश द्वारा उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त किया गया।

उसी वर्ष, अर्थात् 1972 में, उत्तरदाताओं को सीधी भर्ती द्वारा सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन अधिकरण ने पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्तियों की अंतर-वरिष्ठता का निर्धारण करते समय, अपरिवर्तित नियम 26 को लागू किया और अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12 को 1972 में केवल तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्ति मूल आधार पर नहीं थी, इसलिए नियम 26 को ध्यान में रखते हुए वे उन प्रत्यर्थियों से कनिष्ठ होंगे जिन्हें सीधे सहायक अभियंता के रूप में भर्ती किया गया था। न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया कि वे 1976 से ही अपनी

वरिष्ठता की गणना कर सकते हैं जब उन्हें सहायक अभियंता के रूप में पर्याप्त रूप से नियुक्त किया गया था।

सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती का तरीका और विधि नियमों में निहित है। नियम 16 (क) में यह प्रावधान है कि संबंधित विभाग का मुख्य अभियंता वर्ष के दौरान पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों में सेवा में नियुक्ति के लिए जूनियर इंजीनियरों और अधीनस्थ इंजीनियरिंग सेवा के संवर्ग से अधिकारियों को अलग से नामित करेगा। उस नियम में आगे यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य अभियंता द्वारा नामांकन का आधार वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए अधिकारी की योग्यता और उपयुक्तता होगी। नियम 16 (ए) के प्रावधान के अनुसार एक जूनियर इंजीनियर जिसने दो साल की सेवा पूरी नहीं की है, या उप-सहायक इंजीनियर, जो डिप्लोमा धारक नहीं हैं और जिन्होंने दस साल की सेवा पूरी नहीं की है, उन्हें पदोन्नति के लिए नहीं माना जाएगा। दूसरे परंतुक में कहा गया है कि यदि सरकार द्वारा एक परीक्षा निर्धारित की गई थी और उस व्यक्ति द्वारा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई थी, तो उसे पदोन्नति के लिए नहीं माना जाएगा।

पदोन्नति के लिए मुख्य अभियंता द्वारा नामित अधिकारियों की सूची सरकार को भेजी जानी आवश्यक है जहां व्यक्तिगत अधिकारियों के मामलों की विभागीय समिति द्वारा उनके सेवा रिकॉर्ड और यदि आवश्यक हो तो साक्षात्कार के आधार पर जांच की जानी आवश्यक है। विभागीय समिति तब जूनियर इंजीनियरों और उप-सहायक इंजीनियरों की एक अलग सूची तैयार करेगी जिन्हें समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त

माना जाएगा। इसके बाद, सरकार ऐसी सूची उन सभी अधिकारियों के पूर्ण रिकॉर्ड के साथ लोक सेवा आयोग को भेजेगी, जिन्हें पदोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। आयोग तब सूची की जांच करेगा और दो सूचियाँ तैयार करेगा; एक कनिष्ठ अभियंताओं के लिए और दूसरी उप-सहायक अभियंताओं के लिए, जो पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता के क्रम में व्यवस्थित की जाएगी और तदनुसार सरकार को सलाह देगी। नियम 18 के तहत, पदोन्नत किए जाने वाले अधिकारियों का अंतिम चयन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार द्वारा किया जाना है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इन नियमों के आधार पर, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12 को लोक सेवा आयोग की सहमति के अधीन तदर्थ आधार पर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था। यह 8-2-1972 को किया गया था। उड़ीसा लोक सेवा आयोग से सहमति की प्राप्ति पर, 17-7-1976 को एक नई अधिसूचना जारी की गई, जिसके द्वारा अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12 को नियमित आधार पर सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया।

न्यायाधिकरण ने अपने मुख्य निर्णय द्वारा मामले का निपटारा करते हुए, राज्य द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे पर ध्यान

दिया था और यह पाया था कि कोई भी विरोधी पक्ष यह कहने के लिए आगे नहीं आया था कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12 की पदोन्नति उनकी पात्रता के अनुसार नहीं थी और यह विशुद्ध रूप से आकस्मिक प्रकृति का था। इसने आगे कहाः

> ***"राज्य द्वारा दायर काउंटर से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दोनों याचिकाकर्ताओं को स्थायी रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 1972 में पदोन्नत किया गया था और अधिकांश मामलों में, जहां लोक सेवा आयोग की सलाह लेने की आवश्यकता होती है, उन्हें आयोग की सहमति के अधीन तदर्थ पदोन्नति दी गई थी। आयोग से सहमति प्राप्त करने में निश्चित रूप से देरी हुई थी, लेकिन दोनों याचिकाकर्ता राज्य सरकार द्वारा आयोग की सहमति प्राप्त होने तक पदोन्नति के पद पर बने रहे।***

ये तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि अपीलार्थी की पदोन्नति एक नियमित, हालांकि अनंतिम, सेवा नियमों के अनुसार एक स्थायी रिक्ति के खिलाफ की गई पदोन्नति थी। मुख्य अभियंता योग्यता के आधार पर चयन करने के लिए नियमों के तहत अधिकृत अधिकारी थे। तत्काल मामले में, ऐसा चयन मुख्य अभियंता द्वारा किया गया था और आयोग की सहमति लंबित होने पर, चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति सरकार द्वारा तदर्थ आधार पर की गई थी। ऊपर पहले ही यह संकेत दिया जा चुका है कि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन करने का अंतिम अधिकार सरकार के पास है। इस

बात में कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12 को 1972 में सरकार द्वारा सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था और चार साल बाद, अर्थात 1976 में उन्हें उड़ीसा लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उड़ीसा लोक सेवा आयोग की सहमति लंबित रहने तक नियमित, यद्यपि अनंतिम आधार पर पदोन्नत किया गया था। पदोन्नति नियमों के अनुसार किए जाने के कारण, 1972 से 1976 तक की तदर्थ सेवा की पूरी अवधि, जब अपीलार्थी को आयोग की सहमति से नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, को अपीलार्थी की वरिष्ठता के साथ-साथ चुनाव लड़ने वाले प्रत्यर्थियों की वरिष्ठता के रूप में गिना जाएगा। न्यायाधिकरण ने, इन परिस्थितियों में, प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को सही ढंग से लागू किया था। ऑफिसर्स एसोसिएशन। मामला [(1990) 2 एससीसी 715:1990 एससीसी (एल एंड एस) 339: (1990) 13 एटीसी 348: (1990) 2 एससीआर 900: एआईआर 1990 एससी 1607]। इस नियम से भटकने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों (ए) और (बी) में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया हैः (SCC p. 745, para 47)

> ***"47. (ए) एक बार जब किसी पदधारी को नियम के अनुसार किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता को उसकी नियुक्ति की तारीख से***

गिना जाना चाहिए, न कि उसकी पुष्टि की तारीख के अनुसार।

उपर्युक्त नियम का परिणाम यह है कि जहां प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ है और नियमों के अनुसार नहीं है और एक विराम व्यवस्था के रूप में की गई है, ऐसे पद में कार्यपालन को वरिष्ठता पर विचार करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

(ख) यदि प्रारंभिक नियुक्ति नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की जाती है, लेकिन नियुक्त व्यक्ति नियमों के अनुसार अपनी सेवा के नियमितीकरण तक निर्बाध रूप से पद पर बना रहता है, तो कार्यवाहक सेवा की अवधि को गिना जाएगा।

इन सिद्धांतों पर, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया था, और हमारी राय में सही, कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12 प्रत्यर्थियों से वरिष्ठ थे।

ओ..पी. सिंगला बनाम भारत संघ [(1984) 4 एससीसी 450:1984 एससीसी (एल एंड एस) 657] डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग में निर्णय से पहले भी। ऑफिसर्स एसोसिएशन। मामला [(1990) 2 एस. सी. सी. 715:1990 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 339: (1990) 13 ए. टी. सी. 348: (1990) 2 एस. सी. आर. 900: ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1607] 3 न्यायाधीशों

की पीठ ने अभिनिर्धारित किया था कि प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की वरिष्ठता, यदि नियमों के अधीन नियुक्त की जाती है, तो उन तारीखों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए जिन पर प्रत्यक्ष भर्तियों की नियुक्ति की गई थी और उन तारीखों के आधार पर जिनसे पदोन्नतियां अस्थायी पदों पर या मूल रिक्तियों के विरुद्ध लगातार कार्य कर रही थीं। यह इंगित किया जा सकता है कि डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग में संविधान पीठ का निर्णय। ऑफिसर्स एसोसिएशन। मामला [(1990) 2 SCC 715:1990 SCC (L & S) 339: (1990) 13 ATC 348: (1990) 2 SCR 900: AIR 1990 SC 1607] W.B. के राज्य में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया था। v. अघोर नाथ डे [(1993) 3 एससीसी 371:1993 एससीसी (एल एंड एस) 783: (1993) 24 एटीसी 932] और सिद्धांतों (ए) और (बी) को निम्नानुसार समझाया गया थाः (SCC p. 382, para 22)

> *"22. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि इन दोनों निष्कर्षों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए, और निष्कर्ष (बी) उन मामलों को शामिल नहीं कर सकता है जिन्हें निष्कर्ष द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। (A). इसलिए, हम पहले निष्कर्ष का उल्लेख कर सकते हैं (A). निष्कर्ष (ए) से यह स्पष्ट है कि वरिष्ठता को प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से गिना जा सके और पुष्टि की तारीख के अनुसार नहीं, पद के पदधारी को शुरू में 'नियमों के अनुसार' नियुक्त किया जाना चाहिए। निष्कर्ष (क)*

में उपसंहार यह है कि 'जहां प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ है और नियमों के अनुसार नहीं है और एक विराम व्यवस्था के रूप में की गई है, ऐसे पदों में कार्यपालन को वरिष्ठता पर विचार करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है'। इस प्रकार, निष्कर्ष में उपसंहार (ए) स्पष्ट रूप से उन मामलों की श्रेणी को बाहर करता है जहां प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ है और नियमों के अनुसार नहीं है, केवल एक विराम व्यवस्था के रूप में की जा रही है। रिट याचिकाकर्ताओं का मामला पूरी तरह से निष्कर्ष (ए) में इस उपसंहार के भीतर आता है जो कहता है कि वरिष्ठता की गणना के लिए ऐसे पदों में कार्यपालन को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

इसे निम्नानुसार भी समझाया गया थाः

"निष्कर्ष (बी) को एक अलग तरह की स्थिति को कवर करने के लिए जोड़ा गया था, जिसमें नियुक्तियां अन्यथा नियमित होती हैं, नियमों द्वारा निर्धारित कुछ प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की कमी को छोड़कर। यह निष्कर्ष (ख) के प्रारंभिक शब्दों से स्पष्ट है, अर्थात्, 'यदि प्रारंभिक नियुक्ति नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की जाती है' और बाद की अभिव्यक्ति 'नियमों के अनुसार उसकी सेवा के नियमितीकरण तक'। हम निष्कर्ष (ख) को पढ़ते हैं और इसे निष्कर्ष (क) के साथ मिलान करने के लिए इस प्रकार पढ़ा

जाना चाहिए ताकि उन मामलों को शामिल किया जा सके जहां प्रारंभिक नियुक्ति एक मौजूदा रिक्ति के खिलाफ की जाती है, जो नियुक्ति आदेश द्वारा ही समय या उद्देश्य की एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं है, और नियमित होने के समय ठीक किए जा रहे पद के लिए नियुक्ति की उपयुक्तता का निर्णय लेने के लिए नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में कमी के अधीन है, नियुक्त व्यक्ति ऐसे मामलों में प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख पर नियमित नियुक्ति के लिए हर तरह से पात्र और योग्य है। नियुक्ति की प्रकृति के बारे में निर्णय, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह इस श्रेणी में आती है, प्रारंभिक नियुक्ति की शर्तों और नियमों के प्रावधानों के आधार पर किया जाना है। ऐसे मामलों में, नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में कमी को पहले उपलब्ध अवसर पर, कर्मचारी के किसी भी चूक के बिना ठीक किया जाना चाहिए, और नियुक्त व्यक्ति को नियमों के अनुसार अपनी सेवा के नियमित होने तक निर्बाध रूप से पद पर बने रहना चाहिए। ऐसे मामलों में, नियुक्त व्यक्ति अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय नियमों के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में कमी के लिए दोषी नहीं है, और नियुक्ति एक निश्चित अवधि तक सीमित नहीं होने का उद्देश्य एक नियमित नियुक्ति होना है, जो नियमों की शेष प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के अधीन है।

संविधान पीठ के निर्णय का पालन केशव देव बनाम U.P. राज्य में किया गया था। [(1999) 1 एससीसी 280:1999 एससीसी (एल एंड एस) 198] एल. चन्द्रकिशोर सिंह बनाम

मणिपुर राज्य [(1999) 8 एससीसी 287:1999 एससीसी (एल एंड एस) 1460: जेटी (1999) 7 एससी 576]।

पुनरीक्षण कार्यवाहियों में, अधिकरण ने ऊपर निर्धारित सिद्धांतों से विचलन किया, जो हमें कहना चाहिए कि पूरी तरह से अनुचित है और एक निर्णय को फिर से लिखने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा विवाद का अंत में निर्णय लिया गया था। यह, हम यह कहने के लिए विवश हैं, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 22 (3) (च) के अधीन पुनर्विलोकन का दायरा नहीं है जो निम्नानुसार उपबंध करता हैः

"22. (1) -(2)

(3) किसी अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय निहित हैं, अर्थात् -

(ए)-(ई) * * *

(च) अपने निर्णयों की समीक्षा करना;

(छ)-(i) * * * "

ऊपर निकाले गए प्रावधानों से संकेत मिलता है कि न्यायाधिकरण को उपलब्ध समीक्षा की शक्ति वही है जो आदेश 47 सीपीसी के साथ पठित धारा 114 के तहत अदालत को दी गई है। शक्ति निरपेक्ष नहीं है और आदेश 47 में बताए गए प्रतिबंधों से सुरक्षित है। शक्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति के

आवेदन पर नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर किया जा सकता है, जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, उसके ज्ञान में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब आदेश दिया गया था। रिकॉर्ड के सामने दिखाई देने वाली किसी गलती या त्रुटि के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। पुनरीक्षण का दावा नहीं किया जा सकता है या केवल एक नई सुनवाई या तर्क या पहले लिए गए गलत दृष्टिकोण के सुधार के लिए नहीं कहा जा सकता है, अर्थात, पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग केवल कानून या तथ्य की एक पेटेंट त्रुटि के सुधार के लिए किया जा सकता है जो इसे स्थापित करने के लिए किसी विस्तृत तर्क की आवश्यकता के बिना चेहरे पर टकटकी लगाता है। यह इंगित किया जा सकता है कि आदेश 47 नियम 1 में प्रयुक्त "कोई अन्य पर्याप्त कारण" अभिव्यक्ति का अर्थ नियम में निर्दिष्ट कारणों के लिए पर्याप्त रूप से समान है।

प्रत्यक्ष त्रुटि को सुधारने के प्रयास या आदेश 47 में निर्धारित किसी आधार पर आधारित प्रयास को छोड़कर कोई अन्य प्रयास, अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण को अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग होगा।

प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील ने 12-3-1985 को एक समान स्थिति में और उसी सेवा से संबंधित उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय का निर्देश किया है, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए कुछ पदोन्नत अधिकारियों को वरिष्ठता से इस

आधार पर वंचित कर दिया गया था कि तदर्थ पदोन्नति नियमों के विपरीत थी। यह प्रतिवाद किया जाता है कि उस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय द्वारा 28-3-1998 को खारिज कर दी गई थी। आदेश की एक प्रति जिसके द्वारा विशेष अनुमति याचिका खारिज की गई थी, रिकॉर्ड पर रखी गई है जो इंगित करती है कि याचिका को खारिज करने का कोई कारण नहीं दिया गया था। इसलिए, यह आदेश एक बाध्यकारी मिसाल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय 12-3-1985 को दिया गया था, अर्थात् 1990 के प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग II के मामले में संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय से कई वर्ष पूर्व। ऑफिसर्स एसोसिएशन। [(1990) 2 एससीसी 715:1990 एससीसी (एल एंड एस) 339: (1990) 13 एटीसी 348: (1990) 2 एससीआर 900: एआईआर 1990 एससी 1607] संविधान पीठ के निर्णय और इस न्यायालय के अन्य निर्णयों के आधार पर, उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रभावकारिता पूरी तरह से समाप्त हो गई है और पुनरीक्षण निर्णय लिखते समय अधिकरण के लिए संविधान पीठ के निर्णय की अपेक्षा उस निर्णय पर भरोसा करने का कोई अवसर नहीं था।

चुनाव लड़ने वाले उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने कुछ निर्णयों का हवाला दिया है, अर्थात् वी. श्रीनिवास रेड्डी बनाम सरकार। A.P. से। [1995 Supp (1) SCC 572:1995 SCC (L & S) 579: (1995) 29 ATC 495], V.P. श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ M.P. [(1996) 7 SCC 759:1996 SCC (L & S) 670: (1996) 33 ATC 363] और मसूद अख्तर खान बनाम M.P.

[(1990) 4 एससीसी 24:1990 एससीसी (एल एंड एस) 580] लेकिन इनमें से कोई भी निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। वी. श्रीनिवास रेड्डी मामले में इस न्यायालय का निर्णय [1995 सप्लीमेंट (1) एससीसी 572:1995 एससीसी (एल एंड एस) 579: (1995) 29 एटीसी 495] स्पष्ट रूप से विभेदनीय है क्योंकि दो प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच विवाद था, एक को नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया था जबकि दूसरा नियमों का उल्लंघन करता है। तो भी, V.P. में इस न्यायालय का निर्णय। श्रीवास्तव मामला [(1996) 7 एस. सी. सी. 759:1996 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 670: (1996) 33 ए. टी. सी. 363] विशिष्ट है क्योंकि सीधी भर्ती नियमों के अनुसार की गई थी जबकि पदोन्नति उन नियमों के विपरीत की गई थी जो आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं थे। मसूद अख्तर मामले में [(1990) 4 एससीसी 24:1990 एससीसी (एल एंड एस) 580] की गई सीधी भर्तियों को नियमों के विपरीत माना गया था।

प्रत्यर्थियों 2 से 11 के विद्वान वकील ने अनुराधा मुखर्जी बनाम भारत संघ [(1996) 9 एससीसी 59:1996 एससीसी (एल एंड एस) 1187] में इस न्यायालय के एक निर्णय का भी उल्लेख किया। इस प्रस्ताव के लिए कि पदोन्नत व्यक्ति केवल अपनी तदर्थ नियुक्तियों के आधार पर प्रत्यक्ष भर्तियों पर वरिष्ठता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भले ही उन्हें बाद में नियमों के अनुसार चुना और नियुक्त किया गया हो। यह निर्णय इस मामले के तथ्यों पर भी लागू नहीं होता है क्योंकि विद्वान वकील ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देना छोड़ दिया है कि पदोन्नति नियमों का उल्लंघन करने के लिए की गई थी। यह

स्पष्ट है कि यदि पदोन्नति नियमों के विपरीत की जाती है, तो पदोन्नत किए गए लोगों को कोई लाभ नहीं होगा और यह उनके लिए अपनी वरिष्ठता के लिए इस तरह की पदोन्नति की पूरी अवधि को गिनने के लिए खुला नहीं होगा, भले ही उन्हें बाद में नियमों के अनुसार चुना और पदोन्नत किया गया हो।

प्रत्यर्थियों 2 से 11 के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12 प्रत्यर्थियों 2 से 17 के साथ सहायक अभियंता के पदों पर सीधी भर्ती के लिए उड़ीसा लोक सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे, लेकिन वे असफल रहे और इस प्रकार उन्हें वरिष्ठता के मामले में प्रत्यर्थियों पर एक मार्च नहीं दिया जा सकता है। हम सहमत नहीं हैं। प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति प्राप्त करने में विफलता ने पदोन्नति के अपने चैनल में सहायक अभियंता के पदों पर अपीलार्थी और प्रत्यर्थी 12 की पदोन्नति को प्रतिबंधित नहीं किया। वे पात्र थे और परिणामस्वरूप मुख्य अभियंता द्वारा चुने गए और बाद में राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति द्वारा सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किए गए।

चूंकि अधिकरण द्वारा मुख्य निर्णय लिखते समय यह पहले ही एक तथ्य के रूप में पाया गया था कि अपीलार्थी को स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियमों के अनुसार सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था और उसे लोक सेवा आयोग की सहमति लंबित रहने तक तदर्थ पदोन्नति दी गई थी और चूंकि इस निष्कर्ष को हमने ऊपर बरकरार रखा है, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि नियम 26 के संदर्भ में, अपीलार्थी, जिसे 1972 में पदोन्नत किया गया था,

जिस वर्ष प्रत्यर्थियों 2 से 11 की सीधी भर्ती भी की गई थी, प्रत्यर्थियों 2 से 11 तक वरिष्ठ रैंक का होगा।

ऊपर बताए गए कारणों के लिए, अपील की अनुमति है, समीक्षा पर अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और 4-1-1993 के मुख्य निर्णय को बहाल कर दिया गया है, लेकिन लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

Translated by:
Pratik Kumar